4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी

मेरिट के आधार पर तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था हुई चुस्त-दुरुस्त, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का भी रहा पूरा सहयोग

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सरकारी नियुक्तियों और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता का माहौल बना, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ा।

मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने साढ़े चार साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार को अब तक के कार्यकाल में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का भी पूरा सहयोग रहा। मिशन शक्ति पर सीएम ने कहा कि ग्राम सचिवालयों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक कक्ष आरक्षित करते हुए वहां महिला पुलिस बीट अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति, किसानों को अनुदान, उनकी उपज की खरीद का भुगतान सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी की गई राशि लगभग 5 लाख करोड़ रुपये है। योगी ने कहा कि प्रत्येक वृद्धजन, दिव्यांगजन और निराश्रित महिला को पेंशन का लाभ दिलाया गया। ऐसे जरूरतमंद जो भारत सरकार की योजनाओं की पात्रता के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार के अपने संसाधनों से योजना संचालित कर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ-2019 का सफल आयोजन और बाढ़ के दौरान राहत कार्यों का संचालन सरकार की संवेदनशीलता को दिखाते हैं। इसी तरह वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और पहली इनवेस्टर्स समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश को नई पहचान बनाने में सफल रहा।

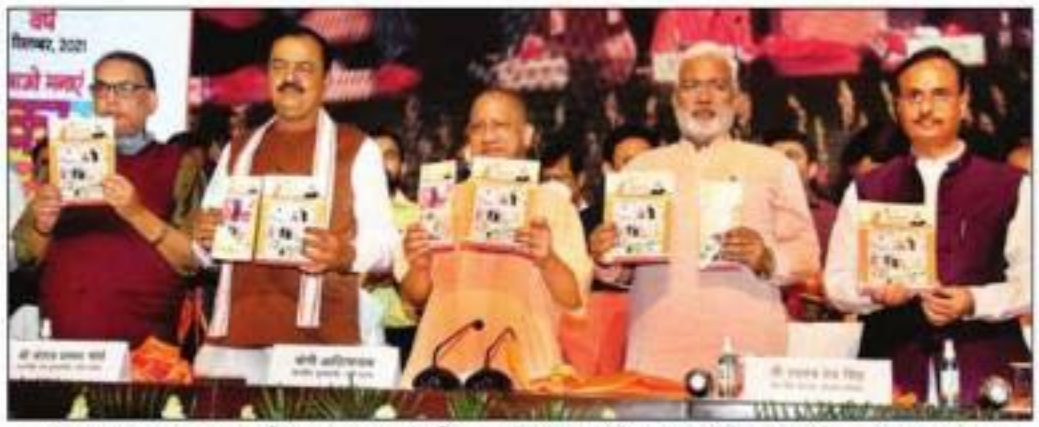

लोकभवन में सरकार की साढ़े चार वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा और यूपी भाजपा प्रभारी राधामोहन सिंह। फोटो : अमर उजाला

शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों का नामकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के नाम पर सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण व उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आभार व्यक्त किया।

विपक्षी दलों को सांप्रदायिकता का लेबल लगने का डर

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अयोध्या, काशी और बरसाना में दीप महोत्सव, देव दीपावली और रंगोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। विपक्षी दल इस तरह के आयोजनों को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखते रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन पर सांप्रदायिक होने का लेबल लग जाएगा।

निवेश से 1.61 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर

कोरोना काल में चीन से निवेश यूपी में आया। डिस्प्ले यूनिट हमारे यहां लगी। इतने बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है कि 1.61 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों को करेंगे लीड

शिक्षा के क्षेत्र में हम 2022 में अग्रणी राज्यों को लीड करते हुए दिखेंगे। 7 नए विश्वविद्यालय और 50 महाविद्यालय बना रहे हैं। पुलिस फोरेंसिंक इंस्टीट्यूट की स्थापना स्थापना लखनऊ में हो रही है। मंडल स्तर फोरेंसिक लैब और साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। 30 हजार महिला आरक्षी भर्ती की गई हैं। 1.26 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा में भर्तियां हुई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से एक करोड़ बहनें स्वावलंबी बनी हैं। यह सब संगठन व सरकार के बेहतर समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व से मिले सहयोग का नतीजा है। मीडिया ने भी हमारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम किया है।

मेट्रो कॉरपोरेशन को मिली पहली बोगी

सीएम ने कहा कि उप्र. मेट्रो कॉरपोरेशन को पहली बोगी बड़ोदरा में मिल चुकी है। नवंबर-दिसंबर तक कानपुर और आगरा में मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष 2017 से पहले यूपी के एक भी शहर में मेट्रो रेल नहीं थी। इतना ही नहीं 'हर गांव सड़क योजना' पर युद्धस्तर पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष वे स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गये थे, लेकिन संक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव आते ही फील्ड में काम करने निकल गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील मुख्यालयों और विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़क मार्गों से जोड़ा जा रहा है। जबकि राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय की सड़कों को फोरलेन किया जा रहा है। प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एव सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर भी मौजूद थे।

दोगुनी केंद्रीय सहायता मिली

उन्होंने कहा कि एमएसपी के तहत किसानों से उनकी उपज की खरीद में ई-पॉप सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। कोरोना काल में भी सभी 119 चीनी मिलें चालू रहीं। केंद्र की सहायता वाली योजनाओं में 2012-17 के मुकाबले 2017-21 तक लगभग दोगुनी सहायता प्राप्त हुई। विगत साढ़े चार वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उज्ज्वला योजना में 1.56 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं, सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 38 लाख से अधिक निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर और 3 करोड़ प्रवासी व निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा गारंटी दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ से अब तक 2 करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,521 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 8 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं।

2.53 करोड़ किसानों को सम्मान निधि

3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर प्रदेश में 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई है। चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियों ने यूपी को निवेश के लिए चुना। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर मृतप्राय हो गया था, पर अब 1.21 लाख करोड़ रुपये का प्रति वर्ष निर्यात कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में विकसित हुआ है।

3 लाख करोड़ का निवेश

योगी ने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। ओडीओपी योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी एवं रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5 से घटकर मार्च 2021 में 4.1 प्रतिशत रह गई।